जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 44 संख्याः 227 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 14 मार्च, 2023 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

अकादमी अवॉर्ड समारोह में तेलुगू फिल्म आर आर आर के गाने ''नाटू-नाटू'' को ''ओरिजनल सॉन्ग'' कैटगरी में ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। आर आर आर के इस गाने ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और एक बार फिर देश को गर्व करने का मौका मिला है। इससे पहले इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड भी मिल चुका है। ऑस्कर अवॉर्ड नाइट में गायक राहुल सिप्लिगुंज और काल भैरव ने स्टेज पर ''नाटू- नाटू'' गाने पर लाइव परफॉरमैंस दी। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद सभी लोग ''नाटू -नाटू'' की धुन पर झूम उठे। संगीतकार एम.एम. कीरावानी का यह गीत पिछले साल अमेरिका में फिल्म की रिलीज़ के बाद ग्लोबल सैन्सेशन बन गया था। हिंदी में यह गाना ''नाचो नाचो'', तमिल में ''नट्टू कूथु'' और कन्नड़ में ''हल्ली नातु'' के रुप में रिलीज किया गया था। अगर नाटू शब्द की बात करें तो इसका मतलब है नाचना। इस गाने में कई अलग-अलग लोगों के नाचने के उदाहरण देते हुए बताया गया है कि, इस तरह नाचिए, जैसे लोकदेवता के किसी फैस्टिवल के लीड डांसर नाचते हैं, जैसे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे नाचते हैं...आदि।

प्रियंका गांधी के पी. ए. संदीप सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

अभिनेत्री व कांग्रेस में सक्रिय अर्चना गौतम के पिता ने यह एफ.आई.आर. उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास दर्ज करवाई है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। प्रियंका गांधी के पी.ए. संदीप सिंह इस समय बहुत बड़े संकट में हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि एक अभिनेत्री तथा कांग्रेस ऐक्टिविस्ट अर्चना गौतम, जो अनुसूचित जाति की भी हैं, की शिकायत पर, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गई है।

- जैसा कि विदित ही है, अर्चना गौतम एक एस.सी. वर्ग की महिला हैं, अतः एस.सी. के व्यक्ति द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. काफी गंभीर मामला बन जाता है।
- इसीलिए संदीप सिंह ने अब कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में शरण ली है, क्योंकि भाजपा की यू.पी. सरकार किसी कांग्रेस के नेता के मामले में थोड़ा भी नरम रूख रखे, इसकी कतई उम्मीद नहीं है।
- प्राप्त जानकारी के अनुसार, संदीप सिंह के खिलाफ पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ बदसलूकी व अपमानजनक भाषा के उपयोग की कई शिकायतें हैं।
- प्रियंका गांधी यू.पी. की इंचार्ज हैं, अतः उनके पी.ए., क्योंकि, वे परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के यू.पी. के मामलों में अपना पूरा दखल रखते हैं, में गुरूर आना स्वाभाविक ही है।
- उनके (संदीप सिंह) के खिलाफ की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अतः अब थक हार कर कांग्रेस नेताओं ने एफ.आई.आर. का रास्ता ढूंढा है।

कानून के तहत, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति और वो भी एक महिला, को परेशान करना तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करना या अपशब्दों का प्रयोग करना गंभीर अपराध है तथा इसमें गिरफ्तारी हो सकती है।

इस आशंका और संभावना के चलते, संदीप सिंह कांग्रेस-शासित राजस्थान में छिपे हुये हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश, जो भाजपा शासित राज्य है, का झुकाव प्रियंका गांधी के स्टाफ के पक्ष में कदापि नहीं होगा।

इस शिकायत पर अर्चना गौतम के पिता ने (मेरठ के पास) उत्तर प्रदेश में एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।

समझा जाता है कि उनके खिलाफ एक से अधिक केस हैं तथा उनके खिलाफ ये केस मूलतः उत्तर प्रदेश के उन कांग्रेसजनों ने दर्ज कराये हैं जो उनकी अकड़, अहंकार और सत्ता की राजनीति के शिकार थे।

प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी हैं और उनके सर्वशक्तिमान पी.ए.के. रूप में, संदीप सिंह उत्तर प्रदेश में पार्टी को चला रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतें नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग तथा उनके दबदबे से संबंधित हैं लेकिन प्रियंका गांधी ने उनके खिलाफ एक शब्द तक सुनने से साफ इंकार कर दिया है। इस प्रकार के परिदृश्य में, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पास पुलिस के पास जाने तथा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के अलावा शायद ही कोई विकल्प बचा है।

सिलिकॉन वैली बैंक के बाद एक और बैंक डूबेगा अमेरिका में?

अमेरिका के ''सिग्नेचर बैंक'' को चलाना संभव नहीं लग रहा, अतः सरकार ''सिस्टमैटिक'' तरीके से इसे बंद करने की दिशा में बढ़ रही है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिका के एक स्टार्ट-अप उन्मुखी बैंक सिलीकॉन वैली बैंक (एस.वी.बी.) के दिवालिएपन ने यह आशंका पैदा कर दी है कि इसका असर भारतीय वित्तीय बाजारों पर भी पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप भारत के शेयर बाजारों में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी।

- हालांकि, इन घटनाओं से हिन्दुस्तान के बैंकिंग सैक्टर को घबराने की खास जरूरत नहीं है।
- पर, इन बैंकों के बंद होने का मनोवैज्ञानिक असर तो जरूर होगा। उदाहरण के लिये, फिलहाल रिज़र्व बैंक ने महंगाई को थामने के लिये, ब्याज दर बढ़ाने का इरादा त्याग दिया है।

जैसा कि इस अखबार में पिछले हफ्ते बताया गया था कि अमेरिकी बैंकों की विफलता भारतीय वित्तीय बाजारों और कुछ स्टार्टअप फर्म्स की संभावनाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल रही है।

दिन में भारतीय स्टॉक मार्केट्स में नरमी का रूख रहा, जिसका निशाना मुख्यतः बैंक और फायनैंशियल कम्पनियों के शेयर रहे। इसकी वजह से इनके बाजार पूंजीकरण में 7 लाख करोड़ रूपयों से अधिक की गिरावट आई। वास्तव में, भारतीय वित्तीय बाजार जापान जैसे वित्तीय बाजार से संकेत ले रहे थे। जापान में सोमवार को बाजार खुलते ही गिरावट का रूख रहा।

स्टार्टअप सैक्टर भी तनावग्रस्त हो गया है क्योंकि कई स्टार्टअप्स ने एक विफल बैंक में अपने फण्ड्स जमा कराए और जमा की पर्ची भी नहीं ली, तथापि इस स्थिति में थोड़ा सा सुधार उस आश्वासन से है, जो अमेरिका के ''फायनैंशियल रैग्युलेटर्स एण्ड डिपोज़िट इंश्योरैंस कारपोरेशन'' ने दिया है। उसने कहा है कि एस.वी.बी. के जमाकर्ताओं को उनका एक-एक पैसा लौटाया जाना चाहिए।

समूचे टैक्नोलॉजी सैक्टर से विपरीत खबर है। इसके अलावा अमेरिका के फैडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में की जा रही निरन्तर वृद्धि ने एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी थी कि उससे बैंकों का असैट बेस धीरे-धीरे कम होने लगा।

एस.वी.बी. के अलावा अमेरिका का एक अन्य ''सिग्नेचर बैंक'' भी ठप्प होने की प्रक्रिया में है। बदलती परिस्थितियों में बैंक के क्रियाकलाप अलाभप्रद हो गए थे, इसलिए सिग्नेचर बैंक के मैनेजमैंट ने इसे व्यवस्थित रूप से बंद करने का निर्णय लिया।

अमेरिका में लगातार दो बैंकों के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'पहली बार देखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी संसद ठप्प करा रही है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। बजट सत्र में दूसरे हिस्से के पहले ही दिन सोमवार को

- कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राहुल के माफीनामा के मुद्दे पर संसद में सत्तारूढ़ पार्टी के हंगामे पर टिप्पणी की।

संसद पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर से मस्जिद हटाई जाए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिए कि तीन माह के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन माह के भीतर हाई कोर्ट परिसर से मस्जिद हटा दी जाए।

परिसर से मस्जिद हटाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वक्फ

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अलवर में बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। केन्द्र सरकार ने तीन और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाने की मंजूरी दी है। ये राजस्थान के अलवर, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाए जाएंगे।

- नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि, राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली व हिमाचल में मंडी सहित कुल तीन शहरों में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

राज्यसभा में नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री रिटायर्ड जनरल डॉ.वी.के. सिंह ने एक लिखित जवाब में दी।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट प्रोजैक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जिसमें

(शेष पृष्ठ 5 पर)

तेलंगाना में विधानसभा चुनावों से पूर्व दरारें पड़ीं भाजपा में

प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय की, मु.मंत्री की पुत्री, के. कविता के खिलाफ हल्की टिप्पणी, तत्कालिक कारण बनी भाजपा नेताओं के आपसी झगड़े का

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। ऐसे समय पर, जब प्रवर्तन निदेशालय ने अपना पूरा ध्यान तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पुत्री के. कविता पर लगा दिया है, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष तथा सांसद बान्दी संजय की ओर से आ रहे अशिष्टतापूर्ण बयानों की जनता द्वारा की जा रही घोर भर्त्सना से राज्य भाजपा इकाई की दरारें उजागर हो गई हैं।

- तेलंगाना भाजपा में अलग-अलग पृष्ठभूमि से कई लोग आये हैं। इन लोगों की विचारधारा, संस्कृति फर्क होने से, मतभेद उभरना तो अपेक्षित सा ही था।
- पर, अगर शुरू से ध्यान नहीं दिया गया व एहतियात नहीं बरता गया तो, ये मतभेद खाई बन सकते हैं तथा भाजपा, जो तेलंगाना में अच्छे नतीजे दिखाने की स्थिति में थी, कहीं लटक नहीं जाये, आंतरिक मतभेदों के कारण।

भाजपा, जो विधानसभा चुनावों तथा लोकसभा चुनावों में तेलंगाना में अपनी अच्छी संभावनाएं मानकर चल रही थी, अब अंदरूनी फूट का सामना कर रही है क्योंकि पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष के कामकाज को लेकर स्थानीय नेताओं के मतभेद सामने आ गये हैं। इसे कोढ़ में खाज ही कहा जायेगा कि भाजपा के वरिष्ठ स्थानीय नेता शेखर राव पेराला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बान्डी संजय पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि संजय मुद्दे उठाते हैं और फिर पैसे बनाने के लिये उन्हे निपटा भी देते हैं। शेखर राव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उनके पास इन आरोपों को सिद्ध करने के सुबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व विभिन्न गतिविधियों की अनदेखी करे तो आदमी को सोशल मीडिया का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ता है।

पेराला ने इस सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, ''आज भाजपा की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह तीन कदम आगे की तरफ चलती है तो छः कदम पीछे की की ओर जाती है और इसके लिये पूरी तरह दोषी राज्य का पार्टी नेतृत्व है।''

भाजपा में, ऐसी चीजें खुले आम प्रचारित नहीं हुआ करती है। लेकिन अगर किसी को सामने आना पड़ता है और ऐसा करना पड़ता है तो इससे केवल यही संकेत मिलता है कि इस समस्या

(शेष पृष्ठ 5 पर)

बी.बी.सी. अपना निर्णय बदलने को मजबूर हुई

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने फुटबाल खिलाड़ी गैरी लिनेकर को पुनः उनकी जिम्मेवारी सौंपी बी.बी.सी. ने

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन (बी.बी.सी.) ने जनता के निरंतर विरोध के आगे झुकते हुए लोकप्रिय स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर गैरी लिनेकर को सेवामुक्त करने के अपने पूर्व के निर्णय को वापस लेकर उन्हें बहाल कर दिया है।

लिनेकर इंग्लैण्ड में फुटबाल के सर्वाधिक लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और वह बी.बी.सी.के हाइऐस्ट पेड प्रैज़ेन्टर थे। जब उन्होंने प्रवासियों के बारे में कन्ज़रवेटिव सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा की तुलना नाज़ी जर्मनी द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा से की थी, तब पिछले शुक्रवार को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। बी.बी.सी. का कहना था कि लिनेकर के ट्वीट ने निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन किया है, जबकि आलोचकों ने उस पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने का आरोप लगाया था।

- लिनेकर नियमित रूप से बी.बी.सी. का अति लोकप्रिय प्रोग्राम ''मैच ऑफ द डे'' प्रैज़ैन्ट करते थे।
- पर, इंगलैण्ड की सरकार द्वारा नयी शरणार्थी नीति को लागू करते हुए, जो भाषा काम में ली गई, उसकी खुली आलोचना करते हुए लिनेकर ने ट्वीट किया कि, यह भाषा नाज़ी सरकार काल में ली गयी घृणित भाषा के समकक्ष है।
- शुक्रवार को इस ट्वीट के बाद, लिनेकर को हटा दिया गया था, पर बी.बी.सी. के स्टाफ ने, बी.बी.सी. के इस आदेश का भारी विरोध जताया, स्पोर्ट्स कार्यक्रम नहीं दिखाये जा सके।
- स्टाफ ने बी.बी.सी. के इस कृत्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात माना।
- डायरैक्टर जनरल टिम डेवी ने हार मानकर सोमवार को घोषणा की कि, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि, लिनेकर पुनः ''मैच ऑफ द डे'' प्रैज़ैन्ट करेंगे।

बी.बी.सी. ने ट्विटर पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर उन्हें निलंबित कर दिया था। इस पोस्ट में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शरण देने की नई नीति की आलोचना की थी।

बी.बी.सी. ने यू.के. सरकार की नई शरण प्राप्ति नीति को लेकर की गई आलोचना से उपजे संकट को समाप्त करते हुए सोमवार को कहा कि गैरी लिनेकर उसके फ्लैगशिप फुटबॉल शो ''मैच ऑफ द डे'' में प्रैजेन्टर के रूप में वापसी करेंगे।

बी.बी.सी. महानिदेशक टिम डेवी ने कहा कि ''गैरी बी.बी.सी. का एक अहम हिस्सा हैं, और मुझे उम्मीद है कि वह आगामी सप्ताहांत में हमारी कवरेज को प्रैज़ैन्ट करेंगे।''

गैरी के ट्वीट और फिर बी.बी.सी. द्वारा उनके निलम्बन के निर्णय के बाद उनके साथी प्रैज़ेन्टर्स, विशेषज्ञों और कमैन्टेटर्स ने उनके समर्थन में उसी सप्ताहांत काम करने से इंकार कर इस बॉडकास्टर की स्पोर्ट्स कवरेज को अस्तव्यस्त कर दिया था।

लिनेकर ने सोमवार को ट्वीट किया कि ''मैं ''मैच ऑफ द डे'' को फिर से प्रज़ैन्ट करने के लिए शनिवार की प्रतीक्षा नहीं कर सकता।''

उन्होंने आगे कहा कि ''हालांकि पिछले कुछ दिन काफी कठिन रहे। इसका ये मतलब नहीं कि ये इतने कठिन रहने हों कि आपको उत्पीड़न वाली जगह से भागकर घर आना पड़ा हो या किसी युद्धभूमि से दूर जाकर कहीं शरण लेनी पड़ी हो।''

डेवी ने सेवाओं में व्यवधान के लिए यह कहते हुए क्षमा मांगी कि ''बी.बी.सी. की सोशल मीडिया गायडैन्स के ग्रे एरियाज़ से बनी भ्रामक स्थिति को वह अब समझते हैं।''

(शेष पृष्ठ 5 पर)

वन रैंक वन पैंशन के किश्तों में भुगतान पर रोक

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को हाथों में लेकर, ऐसे पत्र जारी नहीं कर सकता कि वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) की बकाया राशि (एरियर्स) का भुगतान चार किश्तों में किया जायेगा। मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं जे.बी. पारदीवाला की बैंच ने मंत्रालय से कहा कि वे 20 जनवरी के

- सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का निर्णय सुनाते हुए कहा कि, रक्षा मंत्रालय वन रैंक वन पैंशन के एरियर का भुगतान चार किश्तों में करने की घोषणा कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।

(शेष पृष्ठ 5 पर)